(b) whether he also visited the Scotland Yard; if so, what was the outcome of his discussion with British Police officials; and

(c) what follow-up action has been taken by the Government of India and the U.K. against activities of terrorists in **these two countries**?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) During his recent visit to Britain, the Home Minister discussed with the British Home Secretary the problem of terrorism in Punjab and J. and K. and the need for coordination, liaison and exchange of information between the two countries in this regard. He also visited the headquarters of Scotland Yard and discussed with the British police officials about their system of recruitment, system of policing in Metropolitan cities and methods adopted to fight terrorism etc.

Agitation of Junior Telecom Officers and Gazetted Officers

312. SHRI KAMAL MORARKA:
SHRI YASHWANT SINHA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the main issues for which there was an agitation of junior telecom officers and gazetted officers recently which threw the entire country's telecommunication out of gear;

(b) what are the reasons for which adequate precautions were not taken in spite of notice to ensure continuity of telecom services during the agitation period;

(c) whether it is a fact that Government have agreed to a ratio of 1:1 for promotion of JTOs to Junior Time-scale of Indian Telecom Services Group-A along with direct recruited Junior Time-scale officers as against the present ratio of 1:2;

(d) whether Government have taken into account the serious repercussions that this would have in the next 5 to 10 years in view of the rapid modernisation of the telecommunication network; and

(e) what further steps Government propose to take to ensure that the personnel in the Telecommunication Department are technically qualified to handle modern electric equipment?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Their demands centered around better prospects and further promotional avenues in service.

(b) All possible arrangements were made to ensure continuity of telecom. services during agitation period.

(c) No, Sir. There is an agreed ratio of 1:1 between promoted officers and Direct recruited Junior Time Scale Officers.

(d) Does not arise. There is no change in the agreed ratio of 1:1.

(e) Does not arise. The technical personnel in the Department are being trained as per requirement for future.

"कश्मीर विस्थापित सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे" शीर्षक से समाचार

313. **श्री राम नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जुलाई, 1990 के "जनसत्ता" में "कश्मीर विस्थापित सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो कश्मीर प्रवासियों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन कश्मीरी प्रवासियों में असंतोष के क्या कारण हैं और इस असंतोष को दूर करने के लिए कोई

कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार का घाटी में प्रवासी परिवारों को सुरक्षा देने सहित उपयुक्त हालात बनाए रखने को सुनिश्चित करने के सदैव प्रयास रहे हैं ताकि प्रवासी परिवार वापस आ सकें । जब तक यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक प्रवासी परिवारों को राहत सहायता दी जा रही है ।

जम्मू और दिल्ली में 60,000 से अधिक परिवार पंजीकृत किए गए ।

जम्मू और कश्मीर सरकार और दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रवासियों को दी गयी सहायता का प्रकार और मात्रा संलग्न विवरण में दी गयी । (नीचे देखिए)

विवरण

सरकार द्वारा प्रवासी परिवारों को दी गयी सहायता का प्रकार और मात्रा

प्रवासी परिवारों को सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राहत उपाय निम्नलिखित हैं :—

सामान्य सहायता

उन प्रवासी परिवारों के बच्चों को जो घाटी में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखना चाहते है, घाटी से बाहर के विभिन्न व्यवसायिक और अन्य कालेजों में दाखिले के लिए निर्देश जारी किए गए हैं । घाटी से बाहर, बैंक खातों का स्थानान्तरण, छुट्टियों के वेतन की अदायगी, पेंशन, एल० आई० सी० की किस्त की अदायगी जैसी सुविधाएं भी प्रवासी परिवारों को दी गयी हैं ।

जम्मू में

(1) चार या इससे अधिक सदस्यों के प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1,000 की नकद सहायता देना ।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर मुफ्त राशन की आपूर्ति अर्थात् 9 किलो चावल, 2 किलो आटा, एक किलो चीनी, प्रति परिवार प्रति माह ।

(3) उपलब्ध सरकारी भवनों या टेन्टों में, जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त आवास ।

(4) मुफ्त चिकित्सा सहायता और

(5) जरूरतमंद परिवारों को कम्बलों की आपूर्ति ।

दिल्ली

प्रति व्यक्ति प्रति माह 125 रु० की दर से नकद राहत दी जा रही है बशर्ते कि यह राशि चार सदस्यीय प्रति परिवार प्रतिमास 500 रु० से अधिक न हो ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित तेरह शिविरों में रह रहे प्रवासी परिवारों को नकद राशि के अलावा खाना बनाने के बर्तनों की कोचन किट/बिस्तर और मासिक राशन भी दिया जाता । राशन पर प्रति परिवार होने वाला प्रति माह का व्यय लगभग 500 रु० है । शिविरों में चिकित्सा दल द्वारा नियमित दौरे किए जाने की व्यवस्था भी की गयी है ।

सवाई माधोपुर में दूरदर्शन केन्द्र का प्रतिष्ठापित किया जाना

314. **डा० अबरार अहमद खान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 28 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1931 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इस समय परिवर्तित स्थान पर सवाई